प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

06.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव व चिंता से निपटने को लेकर दिए सुझाव।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–वित्त वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश में नाबार्ड से 7 सौ 13 करोड़ से अधिक की योजनाएं हुईं स्वीकृत।
- विधायक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में आठ जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित।
- विपक्षी भाजपा विधायकों ने विधायक निधि रोकने और विधायकों के पिछली प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।

परीक्षा पे चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर छात्रों को संबोधित किया। नरेन्द्र मोदी ने छात्रों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की अपनी एक अलग शैली होती है, और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम लक्ष्य केवल अंक नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास होना चाहिए।

इधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोक भवन शिमला से वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने शैक्षणिक जीवन में आत्मसात करने का आहवान किया।

सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 के दौरान नाबार्ड से 7 सौ 13 करोड़ 87 लाख रूपए की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। आज शिमला में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए दो दिवसीय बैठकों के तहत आज पहले दिन आठ जिलों ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, चम्बा, लाहौल स्पिति, किन्नौर, सोलन और

बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन स्वीकृत योजनाओं में 5 सौ 12 करोड़ 31 लाख रूपए की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोकनिर्माण विभाग जबकि 2 सौ एक करोड़ 56 लाख रूपए की जलशक्ति विभाग की हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से राज्य को करीब 50 हजार करोड़ रूपए का नुकसान होगा और ऐसे में सरकार को प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। बैठक में सभी विधायकों ने अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित मांगे रखीं।

इस बीच विधायक प्राथमिकता की बैठकों में इस बार भाजपा विधायक भी शामिल हुए। पिछले वर्ष भाजपा विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में आने के लिए विपक्षी विधायकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि सभी विधायकों की मांगे सुनी गई और मौके पर उनके निपटारे के निर्देश दिए गए।

बाईट————सुक्खू, एमएलए मीटिंग

दूसरी तरफ भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर विपक्ष के विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे विकास कार्य ठप्प हो गए हैं।

बीजेपी–ज्ञापन

भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार विपक्षी विधायकों की पिछली प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने और विधायक निधि रोकने का आरोप लगाते हुए आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अक्तूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिससे विधायकों को अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने में मुश्किलें आ रही हैं।

इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अच्छा होता अगर भाजपा विधायक दल प्रदेश के लिए रुके राजस्व घाटा अनुदान–आरडीजी की बहाली के लिए राज्यपाल के पास जाता और हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करता।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है और इस संदर्भ में सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

हर्ष महाजन–सुरेश कश्यप

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चम्बा जिले की पांगी घाटी के लिए हर मौसम में सड़क सम्पर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पांगी घाटी क्षेत्र बर्फबारी के कारण वर्ष में करीब 8 महीने देश के अन्य हिस्सों से कटा रहता

है ऐसे में यहां स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है। हर्ष महाजन ने चम्बा किलाड़, लेह कॉरिडोर को रणनीतिक रक्षा मार्ग घोषित कर बी.आर.ओ. को सौंपने का भी केन्द्र से आग्रह किया। इस बीच लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि देश भर की छावनी परिषदों से जुड़े नागरिक क्षेत्रों को अलग कर निकटवर्ती नगर निकायों में विलय करने की प्रक्रिया को पेश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें भेजे गए अधिकारिक पत्र के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में ये विषय उठाया था जिसके बाद रक्षा मंत्री की तरफ से ये जवाब आया है और इससे छावनी क्षेत्रों के नागरिकों की लम्बित मांग का समाधान हो सकेगा।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में जुब्बल–कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जलापूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, सड़कों और सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जलशक्ति विभाग के तहत करीब 2 सौ 50 करोड़ से अधिक की 94 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव व चिंता से निपटने को लेकर दिए सुझाव।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–वित्त वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश में नाबार्ड से 7 सौ 13 करोड़ से अधिक की योजनाएं हुईं स्वीकृत।
- विधायक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में आठ जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित।
- विपक्षी भाजपा विधायकों ने विधायक निधि रोकने और विधायकों के पिछली प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।

.....